DR. V. MAITREYAN: Sir, is any time-frame for this decision?...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions to be laid. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Is it before the Parliament elections or after the Parliament elections?...*(Interruptions)*...

SHRI C.M. RAMESH: Sir, he has said nothing...*(Interruptions)*... There is no roadmap...*(Interruptions)*...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I may be pardoned for lack of understanding. I am a little more confused than I was at the beginning of the hon. Minister's statement. Do I take it — I want to be clear for my own satisfaction — that various procedural issues from water to services to Hyderabad will all be considered, but that there shall be Telangana is the Government very clear about it?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I made it clear that the decision of the Government is to take forward the process of forming the State of Telangana. That decision has now to be implemented by going through a process. A process takes time. I have the time-table which was followed for Chhattisgarh and Jharkhand. I do not think it should take that long. But, we will have to follow a process. I cannot give a date. All I am saying is the process would be followed as laid down in the Constitution of India and in accordance with past practices.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions to be laid on the Table.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have to seek one clarification...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no...*(Interruptions)*... No, no. I cannot allow...*(Interruptions)*... Now, Special Mentions. Dr. Gyan Prakash Pilania, not present...*(Interruptions)*...

SPECIAL MENTIONS*

Demand to direct the Border Roads Organisation for early construction of Tanakpur-Tawaghat road in Uttarakhand

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (उत्तराखंड) : महोदय, देश की उत्तरी सीमा लद्दाख में चीन भारत की सीमा पर कई बार अन्दर तक घुसपैठ करता आ रहा है। चीन हर दिन तरह-तरह के रूप अख्तियार कर

*Laid on the Table.

[श्री महेन्द्र सिंह माहरा]

भारत की सीमाओं पर तनाव पैदा कर रहा है। चीन पहले भी अरुणाचल पर अपने अधिकार की बात कह चुका है।

इस तरह की घटना कभी भी उत्तराखंड के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में भी घट सकती है, तब हमारे पास अपनी सेनाओं को राज्य की चीनी सीमा पर भेजने के लिए सड़क नहीं होगी, क्योंकि टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग 1963 से 2013 तक 258 किलोमीटर की सड़क पूरी नहीं की जा सकी है। सीमा सड़क संगठन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय सरकारी मशीनरी को दोष दे रहा है। बी.आर.ओ. का कहना है कि वन अधिनियम के कारण वन सम्बन्धी भूमि अधिग्रहण करने के लिए देर से स्वीकृति मिली। जबकि वन अधिनियम, 1980 में लागू हुआ था। निर्माण सामग्री मिलने में कठिनाई, बी.आर.ओ. द्वारा स्वयं पैदा की गई है, क्योंकि उस समय निर्माण सामग्री मिलने में कोई कठिनाई नहीं थी। आज की स्थिति यह है कि टनकपुर से पिथौरागढ़ मुख्यालय तक मोटर मार्ग का निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया है और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव है।

मैं सदन के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के निर्माण में लापरवाही करना भविष्य में होने वाले खतरों से मुंह मोड़ना ही कहा जाएगा, क्योंकि बी.आर.ओ. का कहना है कि इस मार्ग का निर्माण 2019 में पूरा होगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। चीन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में ट्रेन पहुंचा दी, परन्तु हमारी सेना को अपने ही देश के अंतिम चेक पोस्ट लिपुलेक (ऊंचाई 19000 फीट) तक पहुंचने के लिए पैदल की अत्यधिक दुर्गम रास्तों को पार करने में 6 दिन लगते हैं, यह एक बड़ी विडम्बना है। हमारे पास सड़क निर्माण की सभी सुविधाएं होने के बावजूद भी इच्छा शक्ति का अभाव है। यह भी दुनिया का एक बड़ा आश्चर्य होगा - 50 वर्षों में 200 कि.मी. निर्मित मार्ग का सुधार न कर पाना तथा इससे आगे स्वीकृत स्थान लिपुलेक, जो चीन से लगी भारत की अन्तिम चौकी है, वहां तक सड़क न बन पाना।

अत: मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि सीमा सड़क संगठन को सख्त आदेश दिया जाए कि वह टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग का अतिशीघ्र निर्माण करे, जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।

Demand to take urgent measures to check the menace of human trafficking in the country

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : महोदय, युनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एण्ड क्राइम्स (UNODC) की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली मानव व्यापार का एक उभरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनता जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक बात है।

नेपाल, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से बच्चों एवं युवतियों को अच्छी नौकरी का लालच देकर दिल्ली लाया जाता है, पर यहां आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और फिर उनके शोषण का अंतहीन सिलसिला शुरू होता